डिफेंस कॉरिडोर के लिए यूपी में ही तैयार होंगे छोटे उद्यमी

डिफेंस कॉरिडोर के साथ-साथ एमएसएमई कॉरिडोर बनाने पर सहमति, कम से कम 5000 छोटी डिफेंस इकाइयों का होगा जन्म

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। डिफेंस कॉरिडोर की सफलता को देखते हुए एमएसएमई विभाग डिफेंस से जुड़े छोटे उद्यमियों को यूपी में ही तैयार करेगा। डिफेंस कॉरिडोर में बड़ी कंपनियों के संयंत्र शुरू हो गए हैं और कुछ के शुरू होने जा रहे हैं। उनमें कलपुर्जों की सप्लाई के लिए अभी गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की छोटी रक्षा इकाइयों का प्रभाव है। लेकिन डिफेंस की छोटी इकाइयों और उद्यमियों को यूपी में ही तैयार किया जाएगा।

उन्हें सब्सिडी, जमीन से लेकर बाजार तक में मदद सरकार करेगी। कम से कम 5000 छोटी इकाइयों का जन्म डिफेंस के लिए होगा। रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की गई है।

उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़ और झांसी नोड में डिफेंस कॉरिडोर अस्तित्व में आ चुके हैं। इन सभी जिलों में 5000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक 150 से ज्यादा रक्षा क्षेत्र की कंपनियों ने एमओयू किए हैं। 30 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। अकेले कानपुर में 12800 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। करीब ढाई से तीन लाख रोजगार सृजित होंगे।

डिफेंस कॉरिडोर में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, एंकर रिसर्च लैब, जेनसेर, सेल, एमिटेक, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज, आप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, भारत डायनामिक्स लि., एलन एंड एल्वन, उल्टा कॉम्बेट, हंस एनर्जी, स्पाइसजेट टेक्नीक्स, वैरोविन डिफेंस, बीईएमएल, एचएएल, ग्लाइडर्स इंडिया सहित तमाम बड़ी कंपनियां आ रही हैं।

छोटी इकाइयों के लिए सुनहरा अवसर, बनेंगे एमएसएमई कॉरिडोर

बड़ी रक्षा इकाइयां उत्पादों के कलपुर्जे आदि के निर्माण में छोटी इकाइयों की मदद लेती है। एक बड़ी रक्षा इकाई कम से कम 100 इकाइयों को ऑर्डर देती है। अभी अन्य राज्यों में स्थापित एमएसएमई इकाइयों को ये ऑर्डर जाते रहे है। अब यूपी में बड़ी रक्षा इकाइयों से मिलने वाले ऑर्डर के लिए प्रदेश में ही एमएसएमई इकाइयों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए डिफेंस कारिडोर के साथ-साथ एमएसएमई कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। इनमें राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों का लाभ छोटे उद्यमियों को दिया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी में छूट के साथ-साथ उन्हें रक्षा सौदों के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए अलग से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

हर नोड पर इतनी जमीन

लखनऊ : 150 हेक्टेयर, झांसी : 1,034 हेक्टेयर, अलीगढ़ : 84 हेक्टेयर, चित्रकूट : 101 हेक्टेयर व कानपुर : 200 हेक्टेयर

हर नोड में अलग-अलग डिफेंस उत्पादों का निर्माण

- अलीगढ़ : मानवरहित ड्रोन, कलपुर्जों का निर्माण और छोटे हथियारों की इकाइयां मुख्य रूप से स्थापित होंगी
- कानपुर : सेना के लिए विशेष कपड़े और टेक्सटाइल, हथियार, पैराशूट, बुलेटप्रूफ जैकेट व कलपुर्जों की इकाइयां
- झांसी : हथियार, गोला बारूद और परीक्षण केंद्र
- लखनऊ : ब्रह्मोस मिसाइल, एरोस्पेस क्लस्टर और एयरो इंजन क्लस्टर
- चित्रकूट : हथियारों का टेस्टिंग सेंटर
- आगरा : गैर प्रहरणकारी इकाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स

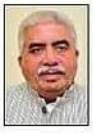

डिफेंस कारिडोर के लिए डिफेंस एमएसएमई कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के छोटे उद्यमियों को रक्षा सौदों के आर्डर लेने के लिए तैयार किया जाएगा। ताकि वहां लगने वाली बड़ी रक्षा इकाइयां प्रदेश में ही छोटी इकाइयों को एंसिलेरी के तौर पर काम दें। इसके लिए औद्योगिक नीतियों के तहत छोटे उद्यमियों को हर तरह की मदद की जाएगी। **-राकेश सचान**, एमएसएमई मंत्री

डिफेंस एक बड़ा सेक्टर है और डिफेंस कॉरिडोर में आने वाली कंपनियों से प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर में अप्रत्याशित बदलाव होगा। बड़ी रक्षा इकाइयां अभी एंसिलरी के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर हैं। इसे देखते हुए राज्य में ही रक्षा इकाइयों के वेंडर तैयार किए जाएंगे। छोटे उद्यमियों को डिफेंस एमएसएमई के तौर पर नया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। **-आलोक कुमार**, प्रमुख सचिव, एमएसएमई